वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 2018 - सितंबर 2019

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद

तकनीकी शिक्षा सदन, बेज नं. 7-12, सेक्टर 4, पंचकूला -134109 (हरियाणा)
दूरभाष : 0172-2570743, अणुडाक : usparishad1@gmail.com

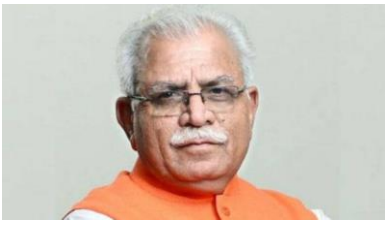

हमारी शिक्षा नीति का मूल तत्व यह है कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता एवं दायित्वबोध की व्यवस्था स्थापित हो। उच्चतर शिक्षा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वह राज्य और राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में प्रत्यक्ष योगदान करें। प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा की दिशा एवं विकास की योजना निर्धारित हो, ऐसी अपेक्षा है।

- **मनोहर लाल**
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार

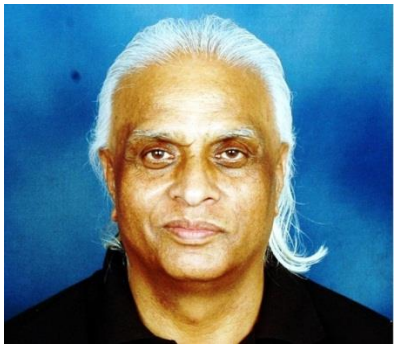

युवाओं को स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज के प्रति दायित्व की भावना से ओतप्रोत करने वाले संस्कार ही वास्तविक शिक्षा है। प्राचीन काल में हुए अनुसंधानों को वर्तमान की आवश्यकताओं से प्रासंगिक बनाने की व्यवस्थाएं बनानी होंगी । शाश्वत मूल्यों की वैज्ञानिकता तभी उपयोगी सिद्ध होगी जब हम अपना विवेक जागृत रखेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों का कार्य युवा वर्ग में ऐसी दक्षता निरंतर सृजित करने का ही है।

- **प्रो. बृज किशोर कुठियाला**

अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद

वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 2018 से सितंबर 2019

क्रमांक	**विषय**
	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन, कर्तव्य और कार्य
	परिषद के उद्देश्य एवं कारण
अध्याय 1	विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व आर्थिक प्रबंधन
अध्याय 2	राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलपति विमर्श
अध्याय 3	पीठों की रचना एवं कार्यप्रणाली पर समीक्षा
अध्याय 4	जीविकोपार्जन
अध्याय 5	हरियाणा की रोजगार क्षमता और उपलब्ध कौशल
अध्याय 6	कानून विश्वविद्यालय : पाठ्यक्रम व न्यायिक शिक्षण की विधियों पर बौद्धिक मंथन
अध्याय 7	प्राचीन दर्शन, ग्रन्थ, संत-महात्मा और ऋषि-मुनियों पर शोध योजना
अध्याय 8	भारतीय भाषाओं की शिक्षा एवं मातृभाषाओं में शिक्षा - योजना व क्रियान्वयन
अध्याय 9	नशा मुक्त भारत : आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एमओयू
अध्याय 10	प्राध्यापक वर्ग का सामाजिक दायित्वबोध
अध्याय 11	अशोक सिंहल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर चिंतन
अध्याय 12	परीक्षा प्रणाली में सुधार
अध्याय 13	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
अध्याय 14	गीता सम्भाषण प्रतियोगिता

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन एवं कार्य

हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा की ओर से 28 फरवरी, 2018 को पारित 'हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018' के अंतर्गत हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद राज्य में उच्चतर शिक्षा की सभी संस्थाओं की स्वायत्तता और वृहत् उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए पॉलिसी सूत्रीकरण और भावी योजना और सामाजिक न्याय प्रोन्नत करने के लिए और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की आवश्यकता के अनुसार राज्य की सामाजिक-आर्थिक अपेक्षाओं के अनुसार उच्चतर शिक्षा के विकास के मार्गदर्शन और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक मामलों के लिए है। इस अधिनियम में परिषद के 20 कर्त्तव्यों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

(1) आयोग के निर्णयों को लागू करना ;

(2) राज्य (भावी योजना, वार्षिक योजना तथा बजट) के लिए उच्चतर शिक्षा की पॉलिसी बनाना ;

(3) योजना तथा कार्यान्यवन में राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता करना।

(4) शीर्ष शिक्षा संस्थानों, नियामक निकायों और राज्य सरकार के बीच समन्वय करना ;

(5) उच्चतर शिक्षा की योजना का अधीक्षण तथा कार्यान्वयन करना ;

(6) प्रबंध करना, सूचना प्रणाली बनाना तथा इसका रख-रखाव करना ;

(7) सरकार के स्तर तथा संस्था के स्तर पर उच्चतर शिक्षा से संबंधित डाटा समय-समय पर संग्रहण करना ;

(8) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन द्वारा बनाई गई मूल अनुपालन सूचना के अनुसार राज्य में उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो मानदण्ड बनाना;

(9) राज्य में अध्यापन गुणवत्ता तथा अनुसंधान में निरंतर वृद्धि के लिए योजना बनाना तथा उपाय सुझाना ;

(10) परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए सुझाव देना ;

(11) समसामयिक तथा सुसंगत पाठ्यक्रम बनाना ;

(12) अनुसंधान में नवपरिवर्तन को बढ़ावा देना।

(13) राज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्ता की सुरक्षा करना ;

(14) नई संस्थाओं, महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना ;

(15) मान्यता की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना ;

(16) उच्चतर शिक्षा में निवेशों के लिए राज्य सरकार को मंत्रणा देना ;

(17) विनियमों तथा अध्यादेशों को बनाने में विश्वविद्यालयों को मंत्रणा देना ;

(18) राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अशंदान के रूप में प्राप्त राशि का प्रबंध करना ;

(19) ऐसी प्रक्रियाएं बनाना जिनके माध्यम से राज्य सरकार की सहायता अनुदान उच्चतर शिक्षा संस्था को अंतरित की जा सकती है ;

(20) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अधीन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों हेतु वित्तीय सहायता के अंतरण की पारदर्शी प्रक्रिया बनाना तथा अनुसरण करना।

परिषद के उद्देश्य एवं कारण

'हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018' का मसौदा पेश करते वक्त शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने इस परिषद गठन के कारण और उद्देश्यों का रेखांकित किया। उनके द्वारा जो कहा गया, वह इस प्रकार है :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अनुशंसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा की योजना एवं समन्वय, स्वायत्त, निष्पक्ष राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के माध्यम से हो। राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना हो जिसमें राज्य सरकार विश्वविद्यालय, शैक्षिक जगत एवं विशेषज्ञों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से उच्चतर शिक्षा के संबंध में समन्वय बन सके, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की उच्च स्तर की नियामक संस्थाओं के साथ सकारात्मक संबंधों का निर्माण हो सके। परिषद की स्थापना से निम्न उद्देश्य पूर्ण होंगे :-

(क) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण एवं भविष्य की योजनाएं बनाकर उच्चतर शिक्षा जगत में सामाजिक न्याय एवं उत्कृष्टता स्थापित हो सके।

(ख) राज्य के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता एवं दायित्वबोध की व्यवस्था बने।

(ग) राज्य एवं राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा की दिशा एवं विकास की योजना निर्धारित हो सके।

अध्याय 1

विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व आर्थिक प्रबंधन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा विश्वविद्यालयों के शीर्ष अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला 8-9 जून, 2018 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 14 विश्वविद्यालयों के कुल 68 शीर्षस्थ अधिकारियों ने सहभागिता की। हर विश्वविद्यालय से कुलपति, कुलसचिव, अधिष्ठाता (Dean) शैक्षणिक, अधिष्ठाता (Dean) महाविद्यालय, परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी अधिकतर उपस्थित थे। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने किया। द्वितीय दिवस का प्रारम्भ माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन से हुआ। प्रधान सचिव (वित्त) ने भी विश्वविद्यालयों के वित्त प्रबंधन की समस्याओं और समाधानों का विषय लिया। कार्यशाला का स्वरूप विमर्श का रहा जिसमें कुल 9 सत्र सामूहिक हुए और एक सत्र में सभी अधिकारियों ने अपने-अपने समूह में विमर्श किया।

सामूहिक सत्रों के विषय:

- सहमति व सहयोग
- स्वायत्तता व जवाबदेही
- वित्त प्रबंधन
- विश्वविद्यालय अधिनियम
- स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की सहभागिता
- मेरे सपनों का हरियाणा - विद्यार्थियों की दृष्टि में

समूहानुसार बैठकों के विषय:

- कुलपति : स्वायतता एवं जवाबदेही
- कुलसचिव समूह : सुरक्षा व सफाई व्यवस्था
- अधिष्ठाता (Dean) शैक्षणिक : पाठ्यक्रम निर्माण
- अधिष्ठाता (Dean) महाविद्यालय : विद्यार्थियों की उपस्थिति
- परीक्षा नियंत्रक : परिणाम व पुनर्मूल्यांकन
- वित्त अधिकारी : वित्तीय अनुशासन

अंतिम सत्र में सामूहिक तौर से कुछ संकल्प लिये गए एवं कार्ययोजना का प्रारूप बना। सभी ने एक मत से इस प्रकार की कार्यशालाओं को बारम्बार करने की अनिवार्यता बताई।

कार्यशाला का बिंदुवार निवेदन इस प्रकार है :-

क. समाधान:

1. राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त आडिट व वित्त कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट विश्वविद्यालय के अधिकारी लिखेंगे।
2. सेवानिवृत्त आडिट विशेषज्ञों को भी राज्य सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।
3. स्नातक स्तर पर Choice based credit system सत्र 2019 से लागू किया जायेगा।

ख. निर्णय:

1. सभी विश्वविद्यालय अपने परिसर व सम्बन्धित महाविद्यालयों में 21 जून, 2018 को योग दिवस का आयोजन करेंगे। इस आयोजन में अधिकतम कर्मचारियों, अधिकारियों, अध्यापकों व विद्यार्थियों की सहभागिता का प्रबंध करेंगे।
2. अध्यापकों, प्रयोगशालाओं एवं अधिकारियों के संसाधनों को सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय आपसी सहयोग व सहभागिता से प्रयोग कर सकें इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों के डीन शैक्षिक की समिति समन्वय करेगी।
3. महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के डीन (महाविद्यालय) की समिति योजना बनाकर प्रयास करेंगी।
4. परीक्षा व परिणाम के विषयों पर शोध करने के लिए दीनबन्धु छोटू राम विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre for Excellence in Examination System) की स्थापना की जायेगी।
5. विश्वविद्यालयों के वित्त प्रबंधन के अनुरूप विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। यह कार्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कम्पयूटर विभाग करेंगे।
6. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का पुनः निर्धारण करते हुए उनमें जीविका उपार्जन एवं जीवन मूल्यों का समावेश किया जाएगा।
7. स्नातक सत्र के हर पाठ्यक्रम मे हरियाणा एवं भारत से सम्बन्धित विषयों का रखा जायेगा।

ग. सुझाव:

1. विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद, वित्त समिति एवं शैक्षिक परिषद के निर्णय ही अंतिम माने जाए।
2. वित्त समिति की बैठक विश्वविद्यालय में ही हो। आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाए।
3. विश्वविद्यालय की समितियों में प्रशासनिक अधिकारियों को नाम से निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाए।
4. महाविद्यालयों से वित्तीय योगदान लेकर हर विश्वविद्यालय शोध के लिए फंड बनाए जिसका उपयोग सम्बन्धित महाविद्यालय के अध्यापक भी कर सकें।
5. विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक का प्रावधान सभी महाविद्यालयों में किया जाए।
6. सुरक्षा एवं सफाई की व्यवस्थाओं को अधिक सुचारू करने के प्रयास किया जाए।

घ. विचारार्थ:

1. हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल 5 वर्ष हो। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों के सम्मेलन में भी ऐसा ही प्रस्ताव है।

2. विश्वविद्यालय के प्रबंधन की टोली (कुलसचिव, डीन शैक्षणिक, डीन महाविद्यालय, प्राक्टर व चीफ वार्डन) की नियुक्ति कुलपति करे एवं उनका कार्यकाल कुलपति के साथ ही समाप्त हो।
3. नव-नियुक्त कुलपति एवं कार्यरत कुलपति एक मास तक मिलकर कार्य करें जिससे हस्तांतरण सहज व सरल हो।
4. ऑनलाइन परीक्षाओं की सम्भावनाएं खोजी जाए।
5. विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षणिक घंटों के अनुसार अध्यापकों की संख्या तय करके उनकी नियुक्ति की जाए। किसी भी समय 10 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के पद रिक्त ना रहे।
6. वित्त प्रबंधन के लिये पीएफएमएस व्यवस्था को अपनाया जाए।

ड़. उलझनें:

1. राज्य में कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए ?
2. तकनीकी और सामान्य विश्वविद्यालयों का विभाजन कितना तार्किक है?
3. राज्य में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या में अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अनुपात कितना और कैसे हो?
4. प्रोटोकॉल में कुलपति, कुलसचिव, प्रधानाचार्य व अधिष्ठाताओं का स्थान क्या हो?
5. विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया क्या हो?
6. राज्य स्तर पर महिलाओं के जीईआर में वृद्धि कैसे हो?

शिक्षा तंत्र की समीक्षा एवं सुधार के लिए बैठक

उच्च शिक्षा तंत्र की समीक्षा एवं सुधार के उद्देश्य से हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने एक बैठक 17 जुलाई 2018 को पंचकूला के रेड बिशप होटल में आयोजित की गई। परिषद अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) श्रीमती ज्योति अरोड़ा, उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

अध्याय 2

राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलपति विमर्श

हरियाणा प्रांत में उच्च शिक्षा को समग्रता से समझने के लिए परिषद ने कुलपतियों एवं अध्यापकों के 6 विमर्श आयोजित कराए। ऐसा यह पहली बार हुआ कि सभी कुलपति, शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय के एकत्रित होकर पारदर्शी और मुक्त विमर्श में शामिल हुए। प्रथम विमर्श में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। प्रांत के विभिन्न विषयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्षों का भी एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालयों के 105 वरिष्ठ अध्यापकों ने भाग लिया। एक अन्य विमर्श में उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने मार्गदर्शन दिया। विमर्श का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 10 उपायों के क्रियान्वयन पर चर्चा करके सुझाव देने का था।

इसी कड़ी में दिनांक 9 और 10 अगस्त 2018 को राजभवन में शासन द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूर्व निश्चित बिंदुओं पर चर्चा हुई। दोनों दिन 3 घंटे से अधिक विमर्श हुआ और पूरा समय माननीय राज्यपाल का सानिध्य प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय यह है कि दोनों दिन के विमर्श में सभी विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप राज्य की उच्च शिक्षा में वर्ष 2018-19 की अध्यतन जानकारी प्राप्त हुई। इस विमर्श में निम्न बिंदुओं पर मुख्य रूप से उभर कर आए:-

1. निजी विश्वविद्यालय और राजकीय विश्वविद्यालय दोनों में ही पाठ्यक्रमों के शुल्क का बहुत बड़ा अंतर है। न्यूनतम शुल्क रुपये 2664/- (एम.डी.यू., रोहतक) और अधिकतम शुल्क 18 लाख रुपये प्रति वर्ष (श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेनटेनरी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम) है।
2. वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष से विद्यार्थी संख्या कम हुई।
3. प्रांत की उच्च शिक्षा में कई विषयों में पूर्व से अधिक विद्यार्थी संख्या का प्रवेश हुआ।
4. राज्यपाल महोदय का सुझाव था कि शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया के विषय में उच्च शिक्षा परिषद को नीति बनाने का सुझाव देना चाहिए।
5. राज्यपाल महोदय का आग्रह था कि विद्यार्थियों का समाज के साथ संवाद एवं सम्पर्क बनाने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए।
6. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों में प्रवेश का आयोजन बहुत सफल नहीं रहा। सुझाव आए कि महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर ही होनी चाहिए।
7. सभी कुलपतियों का यह आग्रह था कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को त्वरित भरने की आवश्यकता है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को इसमें सहायता करने की आवश्यकता है।
8. राज्य में चल रहे बी. एड. शिक्षण महाविद्यालयों का पुनः मूल्यांकन एवं विश्लेषण करके उसके लिए पारदर्शी एवं प्रभावी नीति बनाने का कार्य परिषद को करना चाहिए।
9. राज्य के हर विद्यार्थी को कम से कम 25 घंटे प्रति सप्ताह कक्षा या प्रयोगशाला में सीखने का कार्य करने का कार्यक्रम हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का करना चाहिए।

10. हर विषय में विषय से सम्बन्धित जीविका उर्पाजन का प्रशिक्षण स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए।
11. माननीय राज्यपाल महोदय ने कुलपतियों को सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में भूमि के उपयोग की योजना बनानी चाहिए, जिससे राज्य की सम्पति का पूर्ण रूप से प्रयोग हो सके।
12. जिन विश्वविद्यालयों में भूमि कम है उन्हें और भूमि देने का भी प्रयास होना चाहिए।
13. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को कम से कम एक विषय तय करना चाहिए जिसमें वह विश्वविद्यालय अगले 2-3 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। चयनित विषय की सूचना परिषद को 30 सितम्बर तक भेजी जाए।
14. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने कहा कि हर विश्वविद्यालय किसी एक ऋषि-मुनि या किसी एक भारतीय ग्रन्थ को चिह्नित कर शोध आधारित प्रकाशन अगले 1-2 वर्षों में करें। चयनित ऋषि-मुनि या ग्रन्थ की सूचना 30 सितम्बर, 2018 तक परिषद को भेजें।

विश्वविद्यालयों की स्थापना

वर्ष	संख्या		कुल
	शासकीय वि.वि	निजी वि.वि	
2009 से पूर्व	6	-	6
2009	1	1	2
2010	-	3	3
2011	-	1	1
2012	-	4	4
2013	1	5	6
2014	3	4	7
2015	-	-	-
2016	-	2	2
2017	2	-	2
2018	1	2	3
कुल	14	22	36

विद्यार्थियों की संख्या (रिपोर्ट के अनुसार)

शासकीय वि.वि	निजी वि.वि	कुल
165281	45479	210760

शिक्षक संख्या (रिपोर्ट के अनुसार)

शासकीय वि.वि		निजी वि.वि	कुल
नियमित	अस्थायी	नियमित/अस्थायी	
1589	888	3830	6307

फीस

	शासकीय वि.वि (वार्षिक)	निजी वि.वि (वार्षिक)
अधिकतम फीस	रु. 1,59,900/-	रु. 18 लाख
न्यूनतम फीस	रु. 2664/-	रु. 10,000/-

अध्याय 3

पीठों की रचना एवं कार्यप्रणाली पर समीक्षा

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्थापित पीठों की रचना एवं कार्यप्रणाली पर समीक्षा की है। 10 अगस्त 2018 में महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित उप-कुलपतियों की बैठक में यह विषय ध्यान में लाया गया था। चर्चा के दौरान उप-कुलपतियों द्वारा यह तर्क दिया कि विभिन्न कारणों से स्थापित की गई पीठें न तो पूरी तरह से कार्यशील हैं और न ही इन्हें स्थापित करने के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। अतः उपकुलपतियों द्वारा इस सुझाव पर सहमति बनी कि पीठों के स्थापित करने की जगह पी.पी.पी. मोड में स्टडी सेंटर स्थापित किये जाए।

इसके बाद हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय समीक्षा समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की गई। समिति द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग को जो विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई। इस रिपोर्ट में एक बिंदु विश्वविद्यालयों में स्थापित पीठों के प्रबंधन के बारे में भी था। समिति द्वारा की गई अनुशंसाएं इस प्रकार हैं : -

1. विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित पीठों का विश्वविद्यालय अपने स्तर पर समीक्षा करके उनको चलाये रखना या बंद करने का निर्णय तीन मास में ले लें।

2. पुरानी पीठों को जिनको रखना है और नई पीठों के लिए शोध प्रस्ताव विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जायें।

3. हर पीठ की अवधि निश्चित हो और पीठ से प्रकाशन अनिवार्य हो। पीठ की आर्थिक व्यवस्था समाज द्वारा पोषित हो।

4. सामान्यतः पीठ का प्रस्ताव समाज के किसी वर्ग से आना चाहिए और वही वर्ग उसकी अर्थ व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ले। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय का भी अंशदान हो सकता है।

4. राज्य सरकार भी किसी विश्वविद्यालय को पीठ के माध्यम से शोध कार्य सौंप सकती है, जिसके लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा यह सिफारिशें विश्वविद्यालय को भेज दी गई थी। चूंकि समिति ने कार्यान्वयन बारे कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालयों को चिह्नित किया था इसलिए प्राप्त रिकार्ड अनुसार रोहतक विश्वविद्यायलय ने इन पर विचार किया। और विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने सिफारिशें प्रस्तुति कीं। इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कहा गया कि इन पीठों पर नियुक्त अध्यक्षों और साथ ही पूर्व में कार्यरत अध्यक्षों की एक बैठक बुलाकर उनके विचार भी सीधे प्राप्त किये जाए। तदानुसार एक बैठक दिनांक 30 जुलाई 2019 को आयोजित की गई। इसमें जिन विश्वविद्यालयों के अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया। बाद में विश्वविद्यालयों ने परिषद द्वारा भेजे गये प्रोफॉर्मा पर जानकारी उपलब्ध करवाई।

दिनांक 30 जुलाई 2019 को आयोजित बैठक में प्रत्येक प्रतिभागी से उनके विचार लिये गए और गहराई से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। सभी ने अपने-अपने मत प्रकट किए जिसके आधार पर अंत में सर्वसम्मति से निम्नानुसार सिफारिशें की गईं :-

1. विश्वविद्यालयों में इस समय तक जो पीठें स्थापित की गई हैं उन्हें जारी रखा जाए और इसके लिए जिन पीठों के लिए पद स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत कियें जाए। भविष्य में स्थापित की जाने वाली पीठों की अवधि दस वर्ष रखी जाए। इसी बीच सभी शोध कार्य सम्पन्न किए जाए।

2. विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विभागों में पीठें स्थापित करने की जगह प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शोधकार्य विभाग स्थापित किया जाए। इस विभाग में विश्वविद्यालय के अन्य सभी विभागों मे जो शोध कार्य किये जाते हैं एवं पी.एच.डी. के लिए प्रवेश दिए जाते हैं, उन विषयों पर शोधकार्य की सुविधाएं शोध विभाग में उपलब्ध करवाई जाए। इस तरह जो भी पीठें स्थापित है या भविष्य में स्थापित की जानी हों उनसे सम्बन्धित शोध कार्य भी इसी विभाग को सौंपा जाए। इस प्रयोजन हेतु संसाधन निम्न प्रकार से जुटाएं जाए :-

1. विश्वविद्यालय के अपने बजट में शोध कार्य के लिए राशि का प्रावधान हों वह इस विभाग को आवंटित कर दिया जाए।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा शोधकार्य के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किये जाते हैं और राशि भी स्वीकृत की जाती है। इस बारे में प्रस्ताव शोध कार्य विभाग द्वारा तैयार किये जाए तथा विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. व अन्य संस्थानों के अनुमोदनार्थ एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भेजे जाएं।

3. उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा पीठों की स्थापना के बारे में विज्ञापन दिया जाए, उसके लिए सम्बन्धित संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता, औद्योगिक घरानों व कम्पनियों से सी.एस.आर. के अन्तर्गत फंडिंग प्राप्त की जाए। फिर यदि कोई पीठ स्थापित करनी हो तो उसके लिए विश्वविद्यालयों से सहमति प्राप्त करके अंतिम रूप से चयनित विश्वविद्यालय को उस पीठ के लिए होने वाला शोधकार्य सौंप दिया जाए और फंड आवंटित कर दिये जाए।

4. चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शोधकार्य को महत्व दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की हैं, उसे प्रोत्साहित करने हेतु शोध के लिए ग्रांट-इन-ऐड का अलग मद बनाकर विश्वविद्यालयों को यह राशि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित की जाए।

अध्याय 4

जीविकोपार्जन

रोहतक में 14 सितंबर 2019 को जीविकोपार्जन को लेकर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश भर से चयनित 7 महाविद्यालयों के प्राध्यापक।

स्नातक स्तर पर महाविद्यालयों में जीविकोपार्जन एवं जीवन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने वर्ष भर विषय विशेषज्ञों के साथ विमर्श कर 23 विषयों में निहित आजीविका के 10-10 कार्य बिंदुओं को चिह्नित किया है।

मुख्यमंत्री के सानिध्य में सम्मेलन

इस संबंध में पहला एक दिवसीय सम्मेलन 12 अप्रैल, 2018 को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नैतिक मूल्यों और उन्नत रोजगार के लिये उच्च शिक्षा (Higher Education for Ethical Values and Enhanced Employebility½ विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। श्री राज नेहरू, कुलपति, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम ने श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, श्री रामबिलास शर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, प्रो. बी. के. कुठियाला, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, श्रीमती ज्योति अरोड़ा (तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग) और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रो. बी. के. कुठियाला ने आजीविका के महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत किया और कहा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित आजीविका समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है।

विषय वस्तु बनाने के लिए कार्यशाला

1 जून 2018 को दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत) में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडल के अध्यक्षों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में आधुनिक और रोजगारोन्मुखी विषय वस्तु तैयार करने के लिए कार्यशाला में भाग लिया।

कुलपतियों के साथ खोजे व्यावहारिक उपाय

तदोपरांत इस विषय में एक और महत्वपूर्ण कार्यशाला 15 सितंबर 2018 को पंचकूला में हुई। इसमें प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और 26 प्राध्यापकों सहित 25 विषयों के 33 विशेषज्ञों ने भागीदारी की। इस कार्यशाला में परिषद अध्यक्ष ने इस परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट किया। साथ ही प्रत्येक विषय में ऐसे व्यावहारिक उपाय खोजने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्नातक स्तर के विद्यार्थी जीविका उपार्जन के कार्य करने में समर्थ हों व एक आदर्श नागरिक भी बन सकें।

- इस कार्यशाला में यह भी तय किया गया कि हरियाणा के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में जीविकोपार्जन के व्यावहारिक उपायों का समावेश शैक्षणिक सत्र 2019-20 से सुनिश्चित किया जाए।

32 विशेषज्ञों ने तैयार की विषय-वस्तु

इस विषय को गति देने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला 4 और 5 फरवरी को तकनीकी शिक्षा भवन के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में 23 विषयों के 32 विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

- कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में परिषद अध्यक्ष ने विषय विशेषज्ञों से आग्रह है कि वे अपने विषय से संबंधित कम से कम 10 ऐसे कार्यों को चिह्नित करें जो युवा वर्ग के लिए आजीविका के माध्यम बन सकें।
- दूसरे सत्र में परिषद की ओर से 3 पावर प्वाइंट प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें वाणिज्य, संस्कृत और जन संचार विषयों में निहित जीविकोपार्जन के उपायों पर प्रकाश डाला गया।
- तीसरे सत्र में सभी प्रतिभागियों को विषयानुसार 6 समूहों में बांटा गया। इन समूहों में समान प्रकृति के विषयों को रखा गया, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

समूह रचना

समूह 1 : प्रबंधन, वाणिज्य, पर्यटन

समूह 2 : समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा

समूह 3 : राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास

समूह 4 : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जन-संचार

समूह 5 : भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, संगणक विज्ञान (कम्प्यूटर)

समूह 6 : प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान

इन समूहों में शामिल विद्वानों ने अंतर विषय संभावनाओं को तलाशा। इस दौरान विभिन्न विषयों के परस्पर सहयोग से हो सकने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। समूह चर्चा के बाद सामूहिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में विषय एवं समूह प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी।

कार्यशाला के दूसरे दिन पहले सत्र की शुरुआत में हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी वी. उमा शंकर जी ने प्रतिभागियों के विचार सुने। उन्होंने बहुमूल्य मार्गदर्शन भी किया।

बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें जीवन की गुणवत्ता और समाज-उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल वर्तमान की समस्या बेरोजगारी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें युवाओं को तैयार करना होगा। उन्होंने अंतर्विषय उपायों पर भी जोर दिया। श्री उमाशंकर ने कहा कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषयों के सहयोग से काफी उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बताया गया कि गणित का विद्यार्थी अगर वास्तुकला सीख लें तो वह काफी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इसी प्रकार संस्कृत के विद्यार्थी प्राणी-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कंप्यूटर की जानकारी हासिल कर अच्छे परिणाम दे सकते हैं।

अगले सत्र का एक भाग प्रतिभागियों के अनुभव कथन का रहा। इसमें उन्होंने कार्यशाला के दौरान हुई विषय की स्पष्टता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में भाग लेने से उन्हें दूसरे विषयों की भी स्पष्टता हुई है।

दूसरे दिन के दूसरे सत्र में विषय विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों में निहित रोजगार के उपायों पर प्रकाश डाला। इस दौरान अनेक नए आयामों पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने कहा कि सभी विषयों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं, बस आवश्यकता वर्तमान की जरूरतों को समझते हुए नए तरीके तलाशने की है।

कार्यशाला के समापन सत्र में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने शिक्षाविदों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए- ज्ञान, जीविका और जीवन। पहला, ज्ञान का स्थानांतरण। दूसरा, आजीविका उपार्जन की क्षमता। और तीसरा, समाज में जीवन-मूल्यों की स्थापना। समाज ने यह तीनों जिम्मेदारियां हम शिक्षाविदों को सौंपी है। शिक्षा के माध्यम से समाज का निर्माण कर रहे हैं। हमें यह चिंतन करना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा समाज बना रहे हैं। प्रो. कुठियाला ने कहा कि समाज निर्माण के लिए जब शिक्षा योजना की बात आती है तो शिक्षाविदों को कम से ये पांच बिंदु ध्यान में रखने चाहिए।

1. किसान का परिवार
2. ऊर्जा की बचत
3. मनोरंजन
4. अवशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट)
5. सामाजिक सौहार्द

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि इस दो दिवसीय कार्याशाला में प्रतिभागियों ने जिस निष्ठा से काम करते हुए रोजगार के नये उपायों पर मंथन किया है, निश्चित रूप से वे विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकेंगे। प्रतिभागियों ने तय किया कि वे अपने-अपने विषयों में निहित जीविकोपार्जन संबंधी बिंदुओं को अंतिम रूप देकर 16 फरवरी, 2019 तक परिषद कार्यालय को भेज देंगे।

7 महाविद्याविद्यालयों से शुरुआत

27 अगस्त, 2019 को सोनीपत स्थित जी.वी.एम. महिला महाविद्यालय में उपस्थित 7 महाविद्याविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अपने संस्थानों में इन बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए सहमति जताई।

इससे पहले इस परियोजना के मूल उद्देश्यों के बारे में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेताओं एवं शिक्षाविदों से चर्चा की गई। कार्यक्षेत्र के बदलते स्वरूप परिप्रेक्ष्य में अध्यनरत विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सक्षम बनाने और उन्हें जीवन मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाने इस प्रयास का मूल उद्देश्य है। इस पृष्ठभूमि में परिषद ने इसे कार्यरूप देने के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ अनेक कार्यशालाएं आयोजित की। इसके फलस्वरूप 21 विषयों में जो कार्यबिंदु उभर कर आये वे शिक्षाविदों के साथ साझा किए गए। परिषद ने तय किया कि यह कार्य प्रतिभाशाली प्राचार्यों एवं शिक्षकों के माध्यम से प्रयोगात्मक रूप में स्वेच्छा से शुरू किया जाए। इसके लिए किसी भी शिक्षक या प्राचार्य पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा।

बैठक में प्राचार्यों ने अभियान की रूपरेखा के तीन बिंदुओं (i) अवधारणा (ii) व्यावहारिकता (iii) सुधार पर स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट किए।

सभी ने एकमत से इसकी अवधारणा और व्यवहारिकता के पहलुओं की सराहना की। इसके कार्यान्वयन के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया कि यदि किसी महाविद्यालय में ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी भी विषय में दूसरे महाविद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक लाभान्वित हो सकते हैं तो इस दिशा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या विद्यार्थी व शिक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अपनाया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों को परिषद द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी करने के बारे में विचार किया जा सकता है। अंततः यह निर्णय लिये गये :-

1. प्राचार्य अपने-अपने महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ इस पर विचार-विमर्श करके और जिन विषयों एवं शिक्षकों को इस कार्यक्रम में सहभागी बनाना चाहते हैं उनके नाम, पता, ईमेल एवं मोबाइल नंबर की सूची परिषद को उपलब्ध करवाएंगे।

2. प्राप्त सूची के उपरांत इन शिक्षकों एवं प्राचार्यों के साथ आगामी बैठक किसी शनिवार को जी.वी.एम. महिला महाविद्यालय, सोनीपत में आयोजित की जाएगी।

3. तत्पश्चात इसे इन चुने हुए महाविद्यालयों के प्राचार्य कार्यान्वित करने के बारे में यथोचित कदम उठायेंगे और दिसम्बर में उनके अनुभव आपस में बांटने के लिए परिषद द्वारा बैठक निश्चित की जाएगी।

रोहतक कार्यशाला :

इस विषय में एक और महत्वपूर्ण कार्यशाला रोहतक में 14 सितंबर 2019 को हुई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से चयनित 7 महाविद्यालयों के 43 के प्राध्यापक उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला में प्रदेश भर से चुने महाविद्यार्थियों के प्राचार्यों व प्राध्यापको ने भाग लिया जिसमें एस.डी. कॉलेज अंबाला कैंट से 16 प्राध्यापकों, डी. ए. वी. सैनेटरी महाविद्यालय फरीदाबाद से 13, अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी से 10, एस.डी. महाविद्यालय, करनाल से 15 जी.वी.एस. महिला महाविद्यालय, सोनीपत से 12, एस.डी. महाविद्यालय, हांसी से 9 एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक से 18 ने भाग लिया।

इस कार्यशाला के आयोजन तक हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। 14 सितंबर 2019 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों के प्राध्यापकों ने परिषद अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला की उपस्थिति में अपने-अपने विषयों में आजीविका उपार्जन के तत्वों का समावेश करने का

संकल्प लिया। इससे पहले परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश भर से आए शिक्षकों के सम्मुख बेरोजगारी की समस्या से निपटने के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रो. कुठियाला ने कहा कि विषय अनुसार विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वे स्वयं जीवन चलाने के लिए सक्षम हो। नौकरी व अन्य कार्यों के साथ अपनी आय में वृद्धि करने का उनके पास ज्ञान व साधन अवश्य उपलब्ध हो। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष ने इन महाविद्यालयों से आए शिक्षकों के सम्मुख बेरोजगारी की समस्या से निपटने के आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा है कि कोई भी दायित्वपान शिक्षक अपने पर बेरोजगारों की फौज तैयार करने का आरोप सहन नहीं कर सकता, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अपने दायित्वों को विस्तार देना होगा। कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे प्रत्येक विषय में आजीविका कमाने के तत्व विद्यमान है, जरूरत है कि हमें थोड़ा सा प्रयास कर उन पर अमल करने का है, उन्होंने कहा कि परिषद कर ने एक वर्ष तक विशेषज्ञों की सहायता से प्रयासपूर्वक कार्यों को सूचीबद्ध किया और हर विषय से संबंधित 10-10 व्यावहारिक तत्व खोजे गए, जिनके व्यावहारिक ज्ञान के बल पर कोई भी युवा आसानी से जीविकोपार्जन कर सकता है।

इस अवसर पर मुरथल स्थित दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेन्द्र अनायत ने शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक ज्ञान लाना अति आवश्यक है ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री लालनाथ हिन्दू कॉलेज, रोहतक के प्राचार्य श्री विजय अरोड़ा ने कहा कि हम प्राचार्यों का नैतिक दायित्व बनता है कि समाज कल्याण कार्य उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया ताकि भावी युवा पीढ़ी अपने बल पर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सके।

इसके उपरोक्त प्रत्येक विषय से संबंधित प्राध्यापकों की टोलियां बनायी गईं और सभी टोलियों को अपने-2 विषयों में जीविकोपार्जन के उपायों को कैसे बेहतर तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, चर्चा का समय दिया गया।

अध्याय 5

हरियाणा की रोजगार क्षमता और उपलब्ध कौशल

हरियाणा की रोजगार क्षमता और उसके लिए उपलब्ध कौशल के अंतर का पता लगाने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने तत्त्वावधान में 11 जून 2019 को तकनीकी शिक्षा सदन के सभागार में बौद्धिक विमर्श हुआ। बैठक की पृष्ठभूमि इस प्रकार रही कि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने हरियाणा कौशल मिशन से आग्रह किया कि हरियाणा में विद्यमान रोजगार क्षमता और उसके लिए उपलब्ध कौशल के अंतर को ढूंढ़ना चाहिए। मिशन ने परिषद के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस विषय पर एक प्रस्तुति तैयार की। 11 जून को परिषद की ओर से बुलाई गई बैठक में वरिष्ठ शिक्षाविदों की उपस्थिति में यह प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत इस विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में हरियाणा कौशल मिशन के अध्यक्ष एवं श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 6 विश्वविद्यालयों के कुलपति, विश्वविद्यालयों के प्लेसमेंट अधिकारी, परिषद, कौशल मिशन एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधिकारी मौजूद रहे।

- हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में विद्यमान रोजगार क्षमता और उसके लिए उपलब्ध कौशल के अंतर को ढूंढ़ने की आवश्यकता है।
- हरियाणा कौशल मिशन के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि मिशन इसके लिए योजना बनाएगा, जिसके लिए बैठक में मौजूद शिक्षाविदों के सुझाव अपेक्षित हैं।
- हरियाणा कौशल मिशन की उपनिदेशक ने मिशन द्वारा तैयार किए जा रहे उस प्रस्ताव अध्ययन की पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में हरियाणा में विद्यमान रोजगार क्षमता और उसके लिए उपलब्ध कौशल का ब्योरा दिया गया।
- इसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थान वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनके शिक्षण के तरीकों और औद्योगिक अपेक्षाओं में बड़ा अंतर है।
- शिक्षकों को अपने आप को इस ढंग से तैयार करना होगा कि तेजी से बदल रही तकनीकों को भी वे कुशलता से सिखा सके।
- व्हाइट कॉलर जॉब के लिए हरियाणा से बाहर मौजूद अवसरों पर ध्यान रखना होगा।
- चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे वाणिज्यिक संस्थानों को सहयोग भी अध्यापन कार्यों में लेना चाहिए।
- शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर उद्योगों में भेजना चाहिए ताकि वे वहां की नवीनतम आवश्यकताओं से अवगत हो सके।
- परीक्षा प्रणाली को कौशल केंद्रित बनाना होगा।
- चर्चा के दौरान बताया गया कि हरियाणा के शिक्षण संस्थानों से हर वर्ष करीब 5 लाख युवा उत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन उनमें मात्र एक लाख को ही नौकरियां मिल रही है। शिक्षा जगत को शेष 4 लाख युवाओं के लिए योजना बनानी होगी। शिक्षा और अपेक्षित कौशल के अंतर को पहचान कर ही इस समस्या का निदान हो सकता है।
- रोजगार के लिए सिर्फ उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समाज में मौजूद दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना होगा। तभी युवाओं को समाज उपयोगी बनाया जा सकेगा।

अध्याय 6

कानून विश्वविद्यालय : पाठ्यक्रम व न्यायिक शिक्षण की विधियों पर बौद्धिक मंथन

सोनीपत जिले के राई स्थित डॉ.भीम राव अंबेडकर राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और न्यायिक शिक्षण के तौर तरीके निर्धारित करने के लिए चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शिक्षाविदों और कानूनविदों के साथ बैठक करते परिषद अध्यक्ष।

सोनीपत (राई) स्थित डॉ.भीम राव अंबेडकर राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और न्यायिक शिक्षण के तौर तरीके निर्धारण के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के तत्त्वावधान में तीन बौद्धिक विमर्श हुए।

पहला बौद्धिक विमर्श

यह विमर्श परिषद अध्यक्ष प्रो. बी.के. कुटियाला की अध्यक्षता में 2 मई 2019 को दीनबन्धू छोटूराम विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत) में हुआ। इस विषय 'कानूनी शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन' रहा। प्रो. कुठियाला ने कानूनी शिक्षा प्रणाली में नैतिकता पर जोर दिया और जटिल कानूनी भाषा और कानूनी शर्तों के बजाय आम आदमी की भाषा के उपयोग का आग्रह किया।

इसके साथ ही बौद्धिक विमर्श के दौरान निम्न सुझाव आए :-

- आम आदमी के लिए कानूनी शिक्षा को जानना आसान होना चाहिए।
- सरकार को कानूनों के बारे में जानने के लिए एक एंड्रॉयड एप्लिकेशन बनाना चाहिए।
- कानून का ज्ञान बुनियाद से प्रदान किया जाना चाहिए।

दूसरे सत्र में सभी सदस्यों ने शिक्षण, अभ्यास, सीखने के विषय पर अपने विचार रखे।

तीसरे सत्र में छात्र की रूचि के अनुसार, छात्र को अध्ययन के क्षेत्र यानी कॉर्पोरेट ला, श्रम कानून, आपराधिक कानून आदि का विकल्प चुनने के लिए मौका दिया जाने के लिए कहा गया। डॉ. राजेन्द्र कुमार अनायत ने कहा कि शिक्षण का तरीका पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, परस्पर संवादात्मक आदि में होना चाहिए एवं वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक की उपस्थिति में MOOC एवं SWAYAM पर आधारित शिक्षण होना चाहिए। छात्रों को अपना कौशल बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अदालतों में जाना चाहिए।

डॉ.भीम राव अंबेडकर राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय डॉ. विनय कपूर मेहरा ने छात्रों में नैतिकता, राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में उनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल करने का आश्वासन दिया।

दूसरा बौद्धिक विमर्श

दूसरा बौद्धिक विमर्श 27 जुलाई, 2019 को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर न्यायविदों और शिक्षाविदों के साथ हुआ। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कानून विश्वविद्यालय की कुलपति, हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन, हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश एवं चंडीगढ़ उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के चेयरमैन जस्टिस, हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता और अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शिक्षाविदों और न्यायविदों ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्धारण को लेकर जो सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं :-

- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में सिर्फ कानून की पढ़ाई न करवाई जाए अपितु न्याय व्यवस्था की शिक्षा दी जाए।
- किसी भी देश की न्याय व्यवस्था वहां के उन्नत समाज का एक अंग है, इसलिए इसे वहां के लोगों की जरूरतों के अनुसार ही इसे विकसित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय में भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन होना चाहिए और इस व्यवस्था में निहित न्याय के तत्वों का आधुनिक शिक्षा में समावेश सुनिश्चित करना चाहिए।
- नैतिकता न्यायिक शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए और कानूनों के पालन के साथ सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण भी ध्यान रखने की प्रवृति विकसित हो।
- नैतिकता के धरातल को मजबूत करते हुए विद्यार्थियों को कार्पोरेट की वर्तमान जरूरतों के मुताबिक विद्यार्थियों को तैयार करें।
- राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय को अपने नाम के मुताबिक संविधान निर्माता डॉ.भीम राव अंबेडकर को आदर्श मानते हुए उनके विचार और कार्यों का अध्ययन करवाना चाहिए।
- उपस्थित विद्वानों की राय है कि कानून के विद्यार्थियों को कम से कम 2 भाषाओं में निपुण होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी या अन्य कोई स्थानीय लोकभाषा का अध्ययन होना चाहिए।

तीसरा बौद्धिक विमर्श

तीसरा बौद्धिक विमर्श 28 सितंबर 2019 को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुआ। इस बैठक का विषय 'कानूनी शिक्षा की बहाली' रहा।

इस सत्र में विशेषज्ञों ने जो सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं :-

1. विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम और शिक्षण समाज की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम युवा तैयार करने में हो।
2. वे न केवल सबसे अच्छे अधिवक्ता, बल्कि अच्छे नागरिक बनें। छात्रों के अधिकांश सीखने पर जोर।
3. स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो।
4. विश्वविद्यालय गांवों को गोद लेगा, ताकि जमीनी वास्तविकता को समझा जा सकें।
5. छात्रों में सैद्धांतिक दृष्टिकोण की तुलना में व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित की आवश्यकता है।
6. सामाजिक परिवर्तनों का हिस्सा बनने के लिए कानूनी शिक्षा का उद्देश्य।

7. छात्रों के बीच तथ्यों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए क्योंकि कोई भी दो मामले समान नहीं हैं। यहां तक कि मामूली तथ्य भी मानसिकता बदल सकते हैं।
8. विश्वविद्यालय में कार्यशाला आधारित अध्ययन होना चाहिए, ताकि छात्रों को सही दिशा में जाने में मदद मिल सके।
9. इस क्षेत्र में सॉफ्ट स्किल्स के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।
10. छात्रों को मध्यस्थता, बातचीत, मध्यस्थता - विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों और उनकी आज की आवश्यकता को समझाना चाहिए।
11. छात्रों के लेखन कौशल पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि न्यायाधीशों के साथ तर्क प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है।
12. सीखने के लिए छात्र- अपने लम्बे विचारों / तर्कों को संक्षिप्त शब्दों में कैसे लिखें (सारांश लेखन)
13. एडीआर तंत्र पर ध्यान दें।
14. दोनों सैद्धांतिक पहलुओं (प्रासंगिकता, महत्व, तकनीकी और दोषों को समझने) के साथ-साथ व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें (यह समझना कि कानून वास्तव में किस बारे में है)

अध्याय 7

प्राचीन दर्शन, ग्रन्थ, संत-महात्मा और ऋषि-मुनियों पर शोध की विस्तृत योजना

हरियाणा के विश्वविद्यालयों द्वारा प्राचीन दर्शन, ग्रन्थ, संत-महात्मा और ऋषि-मुनियों पर शोध की विस्तृत योजना बनाने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने 9 अगस्त 2018 को बैठक की। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रांत के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहे। परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि वे कम से कम एक विषय पर आधुनिक प्रासंगिकता वाला ग्रन्थ प्रकाशित करें। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय किसी प्राचीन दर्शन, ग्रन्थ, संत-महात्मा और ऋषि-मुनि पर शोध प्रकाशित करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर शोध के लिए अनुदान का भी प्रबंधन किया जा सकता है। इस संदर्भ में 24 विश्वविद्यालयों से जानकारी परिषद को प्राप्त हुई और शेष को निर्णय लेने में परिषद की ओर से सहायता की जा रही है। इसी संदर्भ में जिस विश्वविद्यालय ने अपने जिम्मे जो शोध कार्य लिया वह इस प्रकार है :-

विश्वविद्यालय	:	विषय
○ गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	:	महर्षि वाल्मीकि
○ स्टारेक्स विश्वविद्यालय, गुरुग्राम	:	आर्यभट्ट
○ महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय	:	वैदिक गणित
○ हरियाणा के अल-फलह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	:	सूफी सिद्धांत
○ एस.आर.एम. विश्वविद्यालय, सोनीपत	:	औषधियों की खोज की प्रक्रिया पर भारतीय दृष्टि

इस बैठक के कुछ समय पश्चात ही 11 राजकीय और 17 निजी विश्वविद्यालयों ने अपने यहां शोध कार्यों की विस्तृत योजना बनाकर परिषद को जानकारी उपलब्ध करवाई। बैठक के बाद जिन विश्वविद्यालय के जानकारी उपलब्ध करवाई, उनका विवरण इस प्रकार है :-

- एमिटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम ने संकल्प लिया है कि वे मनुष्य के शरीर में कौशिका स्तर लिपिड्स के विषय में सर्वश्रेष्ठ शोध केन्द्र बनाने का प्रयास करेंगे।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम ने पारम्परिक भारतीय भोजन बनाने के प्रौद्योगिकी विज्ञान को शोध का विषय चुना।
- जेसीबोस विश्वविद्यालय, फरीदाबाद कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाली प्राकृतिक भाषाओं पर शोध करेगा।
- नार्थकैप विश्वविद्यालय, गुरुग्राम एनीमेशन और गेमिंग पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र बनने का प्रयास करेगा।
- चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी भारत और चीन में पारम्परिक तौर से प्रयोग होने वाली औषधियों पर शोध करेगा।

अध्याय 8

भारतीय भाषाओं की शिक्षा एवं मातृभाषाआ में शिक्षा - योजना व क्रियान्वयन

रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 21 फरवरी 2019 को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से भारतीय भाषाओं की शिक्षा एवं मातृभाषा में शिक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री अतुल कोठारी जी और परिषद अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला जी के साथ उपस्थित प्रतिभागी।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से 'भारतीय भाषाओं की शिक्षा एवं मातृभाषा में शिक्षा : योजना एवं क्रियान्वयन' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला 21 और 22 फरवरी 2019 को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित की गई। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के शुभारंभ मौके पर 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति (अतिरिक्त प्रभार) प्रो. राजबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रो. बृज किशोर कुठियाला मुख्य अतिथि रहे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव एवं भारतीय भाषा मंच के संरक्षक श्री अतुल कोठारी इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे।

इस मौके पर प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए प्रो. बृज किशोर कुठियाला जी ने कहा कि प्रकृति की हर वस्तु में विविधता है। जंगल में कोई भी पेड़ एक सा नहीं है। किसी भी पेड़ के पत्ते एक समान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में मातृभाषाओं की विविधताएं प्रकृति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रो. कुठियाला के अनुसार मातृभाषा मानव मस्तिष्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम से सीखने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम से यह काम सहजता से संभव है।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री अतुल कोठारी ने वहां मौजूद श्रोताओं से संवाद करते हुए कार्यक्रम में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की। इस दौरान अनेक श्रोताओं ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने पर जोर दिया। अनेक श्रोताओं के विचार सुनने के बाद श्री कोठारी ने कहा कि सोशल मीडिया में 87 फीसदी काम भारतीय भाषाओं में हो रहा है और अंग्रेजी भाषा में यह काम मात्र 13 फीसदी रह गया है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं की जड़ें संस्कृत में निहित है। इसलिए उनमें एकत्व का तत्त्व स्वाभाविक रूप से विद्यमान है।

प्रो. कुठियाला के मुताबिक भाषा का विषय केवल भावनात्मक नहीं है, अपितु यह वैज्ञानिक है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति के निरीक्षण की आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा के कारण पं. जवाहर लाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस पद से वंचित करने का प्रसंग भी सुनाया। विषय की अधिक समझ होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा के 22 में से 17 विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया।

भाषाओं के प्रति कितना आग्रह रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोपने पर बांग्लाभाषियों ने अलग देश बना लिया, जिसे आज हम बांग्ला देश के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी भाषा के कारण ही अलग-अलग देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी महत्त्व को समझते हुए 21 फरवरी को 'अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस' घोषित किया हुआ है।

कार्यशाला का प्रथम सत्र :

सार्वजनिक कार्यक्रम एवं भोजन के उपरांत 'भारतीय भाषाओं की शिक्षा एवं मातृभाषा में शिक्षा : योजना एवं क्रियान्वयन' कार्यशाला का पहला सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में लेखक एवं संपादक दिनेश कुमार ने 'भारतीय भाषाओं की शिक्षा' विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि जब 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिब्रू भाषा से 13 नोबेल जीते जा सकते हैं तो फिर उससे कई गुणा ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं के खाते में कहीं ज्यादा उपलब्धियां आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 10 भारतीय भाषाएं हिब्रू से ज्यादा बोली जाती हैं। भारतीय भाषाओं को सीख कर ही विद्यार्थी उनमें विद्यमान राष्ट्रीयता के तत्त्व को समझ सकेंगे। भारतीय भाषाओं में ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। इनमें अनेक विधाओं के ज्ञान की प्रचुरता है। भारत की अनेकता में विद्यमान एकात्म के तत्त्व को भी इन्हीं भाषाओं से समझा जा सकता है। एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखने से राष्ट्रीयता की भावना भी पुष्ट होगी, जो देश की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक है।

इसी सत्र में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद में सह-आचार्य डॉ. सीडीएस कौशल ने मातृभाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में संवाद कौशल दूसरी किसी भाषा से बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही विषय को जिस गहराई से अपनी भाषा में समझा जा सकता है, उतना दूसरी किसी भी भाषा से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों की पहचान भी मातृभाषा के अध्ययन से संभव है।

इसके बाद कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों ने भी भारतीय भाषाओं की शिक्षा एवं मातृभाषा में शिक्षा विषय पर अपने सुझाव दिए। कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :-

- स्नातक कक्षाओं का विद्यार्थी तीन वर्षों में 6 भाषाओं का अध्ययन कर सकता है। इसके लिए इन भाषाओं का साहित्य चिह्नित करना चाहिए।
- शुरू में उन भाषाओं को सिखाया जा सकता है, जिनकी लिपि देवनागरी से मिलती-जुलती है। इसके लिए एड-ऑन कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू कर सकते हैं।
- भारतीय भाषाओं के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जगाने के लिए इसे रोजगार से जोड़ना चाहिए।
- हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक भारतीय भाषा सिखाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस सुझाव पर अमल करते हुए कार्यशाला में उपस्थित मुरथल स्थित दीनबंधु चौ. छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र अनायत ने कहा कि वे अपने विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा सिखाने की व्यवस्था करेंगे।

- प्रतिभागियों ने कहा कि स्नातक स्तर पर विज्ञान सहित अनेक तकनीकी विषय हिंदी में पढ़ाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन विषयों की हिंदी माध्यम की अनेक पुस्तकें हैं।
- इस दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि इन विषयों की हिंदी में पुस्तकें जल्द लिखी जा सकती हैं।
- एक प्रतिभागी ने सुझाव दिया कि पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी तरह से हिंदी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन-संचार ऐसा विषय जिसका पूरा बाजार हिंदी और भारतीय भाषाओं पर ही टिका है। इस विषय का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण इस पेशे का काफी अहित हो रहा है।
- अमेरिका में भारतीय आईआईटीयन से ज्यादा कोरियन आईआईटीयन ज्यादा वेतन पाते हैं। इसका कारण यह है कि कोरियन पेशेवर अपनी पढ़ाई मातृभाषा में करते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि उन्हें अपने पेशे की ज्यादा समझ होगी।

कार्यशाला का दूसरा दिन :

कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने स्नातक स्तर पर हिंदी के क्रियान्वयन के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने के संकल्प भी लिए। इस क्रम में प्रतिभागियों को 4 समूहों में बांटा गया। समूह बैठक में चर्चा के दौरान प्रतिभागियों के संकल्पों का प्रस्तुतिकरण समूह प्रमुखों ने किया। विषय अनुसार समूहों की रचना इस प्रकार रही :-

	समूह	**प्रमुख**
1.	विज्ञान	प्रो. राजीव कुमार
2.	संगणक	डॉ. वजीर नेहरा
3.	भाषाएं	डॉ. सीडीएस कौशल
4.	अन्य	श्री दिनेश कुमार

❖ **विज्ञान से संबंधित पहले समूह में कुल 11 प्रतिभागी शामिल रहे। इन सभी ने जो संकल्प लिए वे इस प्रकार हैं :-**

- **प्रो. ओमप्रभात अग्रवाल (रसायन शास्त्र)**
  - विज्ञान विषयों को हिंदी भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाना। 'भास्कर' तथा 'जल' नाम से पुस्तकों का लेखन।
- **श्री अवस्थी जी (बायो-टेक)**
  - हिंदी में विज्ञान विषय पर लेख लिखना।
- **श्री अशोक शर्मा जी (रसायन शास्त्र)**
  - 6-8 महीने में अपने विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विषय पर हिंदी में संगोष्ठी।
- **श्रीमती सुषमा जोशी (भौतिकी)**
  - अपने विषय पर हिंदी में संगोष्ठी में आयोजन। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम हिंदी में बनाने के लिए।
  - स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार करवाने में सहयोग करेंगे।
  - बी.एससी. प्रथम वर्ष के लिए 'ठोस अवस्था' (Solid State) तथा मैकेनिक्स विषयों के लिए हिंदी में पुस्तकें लिखेंगी।
- **संतोष तिवारी (जेनेटिक्स)**

- भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का डाटा बेस बनाना तथा लेख लिखना तथा लेख लिखना।

- **श्री जेएस सिक्का (गणित)**
  - वैदिक गणित पर कार्यशाला करना। इस विषय में डॉ. राजीव के काम में सहयोग करना।
- **श्री राकेश भाटिया (गणित)**
  - दूरस्थ शिक्षा के लिए गणित का पाठ्यक्रम बनाना। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम की रचना करना।
  - वैदिक गणित पर वीडियो तथा ऑनलाइन सामग्री बनाना।
- **श्री राकेश श्योराण (भौतिकी)**
  - विज्ञान स्नातक (बीएस.सी) प्रथम वर्ष के लिए विद्युत तथा चुम्बकीय विषयों पर हिंदी में पुस्तक लिखना।
- **श्री जय प्रकाश (भौतिकी)**
  - शोध पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना।
  - बी.एस.सी तृतीय वर्ष के लिए नाभिकीय भौतिकी (न्यूक्लीयर फीजिक्स) विषय पर पुस्तक लिखना।
- **श्री अश्विनी (बायो-टेक)**
  - हिंदी में शोध पत्र लिखना।
- **प्रो. राजीव कुमार (गणित)**
  - 'भारतीयों का गणित में विकास' विषय पर लेख लिखना।
  - 'प्रायिकता तथा सांख्यिकी' विषय पर हिंदी में पुस्तक लिखने का प्रयास।

❖ **दूसरे समूह में कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित 3 प्रतिभागी शामिल रहे। इन्होंने जो संकल्प लिए उनका विवरण इस प्रकार है:-**

- **सुश्री नरेश गिल (सोनीपत)**
  - बहुतकनीकी शिक्षा संस्थान में प्रथम वर्ष डिप्लोमा में पढ़ाए जाने वाले विषय को हिंदी में तैयार करेंगी।
- **सुश्री महिमा (गुरुग्राम)**
  - कंप्यूटर विज्ञान की तकनीकी शब्दावली का हिंदी संस्करण तैयार करेंगी। इन्होंने अपनी कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान को हिंदी माध्यम से पढ़ाने का भी संकल्प लिया है। महिमा ने सुश्री नरेश गिल के साथ मिल कर हिंदी सॉफ्टवेयर तैयार करने पर भी सहमति जताई है।

❖ **तीसरे समूह में भाषा विषयों से संबंधित 5 प्रतिभागी शामिल रहे। इन सभी ने जो संकल्प लिए वे इस प्रकार हैं :-**

- **प्रो. रामरति मलिक (रोहतक)**
  - हरियाणवी मुहावरों और लोकोक्तियों का संकलन कर पुस्तक तैयार करेंगी।
- **प्रो. अनिल कुमार (रोहतक)**
  - हरियाणा के कवियों का संक्षिप्त परिचय, भारतीय साहित्य के माध्यम से विविध भाषाओं का परिचयात्मक अध्ययन और हिंदी भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल विषयों पर 3 पुस्तकें लिखेंगे।
- **प्रो. बाबू राम (भिवानी)**

- हरियाणा का सन्त साहित्य, हरियाणवी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विषय पर पुस्तक लिखने का संकल्प लिया है।

- **डॉ. ममता ओझा (इन्दौर, म.प्र.)**
  - संचार के प्रारूप, जनसम्पर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय संचार विषय पर हिंदी में पुस्तक लिखेंगी।
- **डॉ. सीडीएस कौशल (पंचकूला)**
  - संस्कृति-मंथन (भारतीय संस्कृति-विविध भाषाओं में) विषय पर पुस्तक लिखी जाएगी।

❖ चौथे समूह में प्रबंधन, इलेक्ट्रोनिक्स और जन-संचार विषयों के कुल 6 प्रतिभागी शामिल रहे। इनके संकल्प इस प्रकार हैं :-

- **प्रो. राजीव चंद्र शर्मा (अंबाला छावनी)**
  - 'कार्यालय प्रबंधन : सचिवीय पद्धति' विषय पर हिंदी में एक वर्ष के भीतर एक पुस्तक लिखेंगे। इस पुस्तक में कम्प्यूटर में हिंदी प्रयोग पर तकनीकी जानकारी भी होगी।
- **डॉ. कंचन (गुरुग्राम)**
  - 'प्रबंधन की भारतीय दृष्टि' विषय पर पुस्तक लिखने का संकल्प लिया है। इस पुस्तक में प्रबंधन के नये आयामों पर भी चर्चा होगी। 8 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
- **सुश्री ईशा गोयल (गुरुग्राम)**
  - गुरुग्राम स्थित कंपनियों से बात कर उन्हें हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तवज्जो देने का आग्रह किया जाएगा। चालू अकादमिक सत्र में एक सेमिनार करवाने का प्रयास रहेगा।
- **प्रो. प्रदीप डिमरी (फरीदाबाद)**
  - इलेक्ट्रोनिक्स विषय पर डिप्लोमा स्तरीय पुस्तक लिखना तय किया है। इस पुस्तक में वर्तमान की जरूरतों के मुताबिक विषयवस्तु शामिल होगी।
- **डॉ. कुलदीप कुमार (भिवानी)**
  - स्नातक स्तर पर पढ़ाने के लिए 'भारत की विदेश नीति' विषय पर राजनीति विज्ञान आधारित एक पुस्तक लिखेंगे।

कार्यशाला के दूसरे दिन प्रो.कुठियाला जी ने स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा के क्रियान्वयन के लिए जो मार्गदर्शन किया, उसमें निम्न बिंदु प्रमुख रूप से शामिल रहे।

1. हर विषय का पाठ्यक्रम हिंदी में भी हो।
2. समय सारणी हिंदी में तैयार करें।
3. गृहकार्य अपनी मातृभाषा में दें।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय एक भारतीय भाषा का अध्ययन करवाएं।
5. स्नातक स्तर की परीक्षा का हिंदी में विकल्प हो।
6. संचार कौशल विकसित करते हुए विद्यार्थियों को द्विभाषी बनाएं।

कार्यशाला के अंतिम सत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव एवं भारतीय भाषा मंच के संरक्षक श्री अतुल कोठारी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस सत्र की शुरुआत उन्होंने 3 बार ॐ के उच्चारण और प्राणायाम से करवाई। उन्होंने ॐ के

उच्चारण का महत्व बताते हुए कहा कि इससे एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ उन्होंने 'तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय ….' प्रार्थना का विस्तार से अर्थ भी समझाया।

- श्री कोठारी जी ने कहा कि यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है कि किसी भी देश की शिक्षा वहां की संस्कृति और विकास की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए।
- उन्होंने कहा कि ताजी हवाओं के लिए खिड़कियां तो खुली रखनी चाहिए, लेकिन हवा इतनी भी नहीं आनी चाहिए कि पैर जमीन पर ही न लग पाए।
- योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों की सहभागिता जरूरी है। इसके लिए आम सहमति भी जरूरी है। लोगों पर थोपी जाने वाली योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाती। पंचवर्षीय योजनाओं का ऐसा ही हाल हुआ है।
- संकल्प से सफलता संभव है। यह नियम व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में भी लागू होता है।
- अगर किसी ने कुछ विशेष काम किया है, उस पर दूसरों की प्रतिक्रिया का भी सम्मान करना चाहिए।
- पाठ्यक्रम पर चर्चा से सतत सुधार की गुजाइंश रहती है। उदाहरण – विवेकानंद के दृष्टिकोण का उच्च शिक्षा में समावेश पर पुस्तक का उदाहरण।
- भाषा के क्षेत्र में देशव्यापी जनजागरण अभियान की जरूरत है। बार-बार झूठ का प्रचार करके गलत चीजें स्थापित की गई है।
- हिंदी पखवाड़ा, अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस आदि मौकों पर कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें।

<u>कार्य करते वक्त तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए :-</u>

1. पहले करो, फिर बोलो। (ऋषि मुनियों के प्रयोग)
2. वैज्ञानिक और तार्किक बात करें।
3. तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए।

- हर दिन नया सीखने का प्रयास होना चाहिए। लंबा अनुभव होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़ी मात्रा में खड़े पानी से झरने का बहता थोड़ा पानी भी ज्यादा उपयोगी रहता है।
- सुख, मजा और खुशी में अंतर है। आनंद कष्ट में भी सुख देता है।
- निस्वार्थ से कोई भी कार्य करना अध्यात्म है : स्वामी विवेकानंद।
- स्वयं को पहचानें, आत्म निरीक्षण करें। सभी महापुरुष अपने अंदर देखते थे।
- पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी करने वालों को प्लास्टिक के कप में चाय पीते देखा जाता है।
- महर्षि रमण के मौन सत्र का उदाहरण। विनोबा भावे के मुताबिक स्वयं के आचरण से सिखाने वाले को आचार्य कहते हैं।
- ऐसे ही मेहनत से लगे रहे। चार-पांच साल में सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर निरंतर काम में लगे रहे।

अध्याय 9

नशा मुक्त भारत : आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एमओयू

हिसार स्थित गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में 19 फरवरी 2019 को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते श्रीश्री रविशंकर जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, परिषद अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला और सुप्रतिष्ठित खिलाड़ी एवं कलाकार।

युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत करवाने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने 19 फरवरी 2019 को हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में विश्व विख्यात आध्यात्मिक संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एमओयू किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में परिषद की ओर से अध्यक्ष प्रो. बृजकिशोर कुठियाला और आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से श्रीश्री रविशंकर ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययरत युवा छात्र-छात्राओं के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से छात्र-छात्राओं के साथ-साथ लोकप्रिय कलाकार व खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। प्रदेश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के निवेदन को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को इंटरनेट के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के लिए इसके सीधा प्रसारण की व्यवस्था भी की।

अध्याय 10

प्राध्यापक वर्ग का सामाजिक दायित्वबोध

भिवानी स्थित चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय में 15 सितंबर 2019 को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से प्राध्यापक वर्ग का सामाजिक दायित्व बोध विषय पर आयोजित संगोष्ठी में परिषद अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला जी का परिचय करवाते विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. जितेंद्र भारद्वाज। मध्य में उपस्थित हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल।

उद्देश्य : शिक्षक वर्ग के सामाजिक सरोकार बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। वे लोगों में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के साथ विकास योजनाओं में भी सहभागी बनेंगे।

योजना : योजना के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के चयनित प्राध्यापक महीने में कम से कम दो दिन और एक रात के लिए गांव में ठहरेंगे। प्रारम्भिक स्तर पर इन्हें **'शिक्षा मित्र'** और बाद में 'विकास मित्र' की संज्ञा दी जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके तीन काम प्रमुख होंगे :

1. संपर्क
2. संवाद

3. संबंध

यह कार्य पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा भावना पर आधारित है।

इस अभियान से जुड़ने वाले प्राध्यापकों से 3 प्रमुख अपेक्षाएं :

1. स्वप्रेरणा से काम में लगना।
2. निजी समय और निजी धन का प्रयोग करना।
3. निस्वार्थ भावना से कार्य करना। इसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखना।

बैठकें/सम्मेलन :

1 दिसंबर, 2018 को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 103 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रो. बी.के. कुठियाला, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद कार्यशाला के मुख्य अतिथि रहे। प्रो. आर. बी. सोलंकी, कुलपति (सी.आर.एस.यू.) ने अध्यक्षता की।

16 फरवरी, 2019 को परिषद कार्यालय में "प्राध्यापक वर्ग का सामाजिक दायित्वबोध' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् श्री अनिरुद्ध देशपांडे और परिषद अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। कार्यशाला में कुल 44 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

कुलपति सम्मेलन : 11 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में प्रदेश के सभी कुलपतियों ने इस अभियान में सक्रिय सहयोग देने का विश्वास दिलाया। *(सम्मेलन का विस्तृत ब्योरा इस अध्याय के अंत में दिया गया है।)*

विस्तार :

- 7 अप्रैल, 2019 को कुरुक्षेत्र में आयोजित बैठक में इस अभियान के कार्य विस्तार की योजना बनी।
- हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में कुल 140 विकास खंड हैं। परिषद की योजना है कि इन 140 खंडों से ही इस अभियान की शुरुआत की जाए।
- विस्तार योजना के तहत अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी में बैठकें हो चुकी हैं।
- जल्द ही करनाल, खानपुर, मीरपुर, महेंद्रगढ़, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में बैठकें होनी हैं।

16 फरवरी 2019 की कार्यशाला का विस्तृत ब्योरा

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने 16 फरवरी 2019 को पंचकूला के सेक्टर-4 स्थित परिषद कार्यालय में 'प्राध्यापक वर्ग का सामाजिक दायित्वबोध' विषय पर कार्याशाला का आयोजन किया। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. अनिरुद्ध देशपाण्डे और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। दो सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला में कुल 44 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि समाज ने अध्यापक वर्ग को विशेष स्थान दिया है। इस वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा, आय का स्तर एवं समाज में विश्वास सभी कुछ विशिष्ट है। इन विशिष्टताओं का समाजहित में प्रयोग होना चाहिए।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् प्रो. अनिरुद्ध देशपाण्डे ने कहा कि प्राध्यापक वर्ग समाज का विशिष्ट घटक है। समाज की विशिष्ट रचना में शिक्षक वर्ग का विशिष्ट स्थान है। महाराष्ट्र में शिक्षक को पंत जी कहते हैं। वहां पंत जी का काम निस्वार्थ भाव से सलाह देना है।

- शिक्षक अघोषित रूप से समाज का नेतृत्व करता है।
- समाज का बौद्धिक उन्नयन करता है।
- स्वामी विवेकानंद के मुताबिक शिक्षक की प्रमुख भूमिका इस प्रकार है :- मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण, बुद्धि का विस्तार, शक्ति स्थापना।
- किसान, व्यापारी या दूसरे कर्मचारी यह काम नहीं कर सकते।
- यह बातें अब सिर्फ भाषणों तक सीमित न रहें।
- इसके लिए उचित वातावरण है क्या? पीढ़ियों का अंतराल होने के कारण अनेक चीजें प्रभावित हो रही हैं।
- पुरानी चीजों के प्रति अविश्वास पैदा किया जा रहा है।
- पुराने मूल्यों का अवमूल्यन किया जा रहा है।
- जो पढ़ रहे हैं, उसे जानना भी चाहिए।
- बाह्य जगत में परिवर्तन हुए हैं।
- तकनीक से ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बदलने लगे हैं।
- व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया करने वाले पाठ्यक्रम बनाने होंगे।
- उदाहरण के तौर पर 22 में से 20 विद्यार्थी 'वंदे मातरम्' के रचयिता का नाम नहीं बता पाए।
- संवेदनशीलता का अभाव।
- समाज का चित्रण करना। जैसा है वैसा बताने की आवश्यकता है।
- 2035 तक 50 फीसदी लक्ष्य।
- चिंतन का तत्त्व होना चाहिए, लेकिन सूचना पर आधारित।
- सामाजिक सद्भाव जरूरी है।
- विडंबना यह है कि अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा मानने लगे हैं। समाज के प्रति प्रतिबद्धता हो।
- जातीय प्रतिद्वंद्व समाज और कॉलेज में प्रदर्शनी का विषय हो सकते हैं क्या?
- सह-पाठ्य गतिविधियां कम हो गई हैं।
- राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को मूर्त रूप दें।

इस व्याख्यान के बाद प्रतिभागियों ने भी चर्चा में सहभागिता की।

- जींद से ज्योति श्योराण ने अनुभूति प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी।
- डॉ. विनय कपूर ने कहा हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी काम शुरू कर देना चाहिए। उदाहरण : अकेला इंजन भी पूरी रेलगाड़ी को खींच सकता है।
- कुरुक्षेत्र के एनआईटी से प्रो. अजय जांगड़ा के मुताबिक विद्यार्थियों को प्रोडक्ट न बनाएं बल्कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरें।
- प्रो. ऋषि पाल ने कहा कि युवा पीढ़ी में माता-पिता, दादा-दादी के प्रति सम्मान की भावना जागृत करनी होगी।
- रोहतक स्थित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से आए प्रो. संतोष तिवारी ने कहा कि शिक्षकों में प्रतिबद्धता की भावना में कमी आई है। इस कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा में भारतीयता की भावना भी भरनी होगी।
- यमुनानगर के डॉ. उदयभान के मुताबिक लोगों को अपने आस-पड़ोस के प्रति अधिक सामाजिक होना चाहिए। फिलहाल हालात यह है कि लोगों को अमेरिका का तो पता चल जाता है, लेकिन अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रहता।

समापन सत्र में प्रो. बृज किशोर कुठियाला जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके उद्बोधन के संक्षिप्त बिंदु इस प्रकार हैं :-

- सिर्फ पढ़ाने तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिखाने का काम करना होगा। लाइफ काउंसिलिंग और कॅरियर काउंसिलिंग के अंतर को समझना होगा।
- यह भी समझना होगा कि हमें एकता चाहिए या एकात्मकता।
- शिक्षक वर्ग को विषय केंद्रित बनना होगा।
- समस्याओं की जड़ें गहरी हैं। अकेला चलने से काम नहीं चलेगा। अकेले काम कर सकते हैं, ऐसा करने वालों की भी हम मदद करेंगे।
- छोटी संख्या से बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या से कम काम करना हमें मंजूर नहीं।

<u>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कुलपतियों के विमर्श का ब्योरा</u>

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का विमर्श भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के परिसर में आयोजित हुआ। इसमें हरियाणा के राजकीय एवं निजी, सभी विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सहभागिता रही। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से भी प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता की। विमर्श के संक्षिप्त बिंदु इस प्रकार रहे हैं :-

1. उद्घाटन सत्र में उन्नत भारत अभियान 1 और 2 के उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली की विस्तृत प्रस्तुति हुई। उन्नत भारत अभियान को राज्यों के अनुसार क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

2. चर्चा में विषय आया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के कुलपति, निदेशक व प्राचार्य शिक्षा जगत को योग्य नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्राध्यापक समाज के विशिष्ठ व्यक्तियों में है क्योंकि वे सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक ज्ञानी होते हैं। उनके पास ज्ञान के स्रोतों की सर्वाधिक

जानकारी और पहुंच होती है। प्राध्यापकों का संवाद कौशल भी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। वास्तविकता यह भी है कि हर वर्ष युवाओं की एक नई पीढ़ी प्राध्यापकों के पास लगातार आती है। शिक्षण संस्थाओं में सब समाज का ही दिया हुआ है। इस दृष्टि से शिक्षण संस्थाओं एवं प्राध्यापकों का दायित्व है कि वे शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त भी समाज के विकास में अपना योगदान करें। उन्नत भारत अभियान की यही कल्पना है।

3. दूसरे सत्र में 'उन्नत महाराष्ट अभियान' की प्रस्तुति स्काईप के माध्यम से हुई। इस बात की जानकारी मिली की किस प्रकार से महाराष्ट्र में कॉलेज और विश्वविद्यालय आस-पास के क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बना रहें है और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान खोजने में प्रयासशील है।

4. तीसरे सत्र में मुक्त चर्चा हुई और उपस्थित सभी विद्वानों ने उन्नत भारत अभियान को किस प्रकार हरियाणा के परिपेक्ष्य में लागू किया जा सकता है, पर विस्तृत चर्चा हुई। इसलिये सत्र का समय बढ़ाया गया।

5. समापन सत्र में निम्न विषयों पर सहमति बनीः-

- सभी विश्वविद्यालय हरियाणा प्रांत की विकास की परिकल्पना, योजना बनाने में सहयोग करें।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करके वहां की विशेषताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं व समस्याओं की रिपोर्ट बनायें।
- निजी विश्वविद्यालय भी अपने आस-पास के क्षेत्रों का इसी दृष्टि से अध्ययन करें।
- क्षेत्रों का वितरण उच्च शिक्षा परिषद के सहयोग से किया जाए।
- सभी विश्वविद्यालयों की अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर उच्च शिक्षा परिषद हरियाणा प्रांत के लिए विकास की परिकल्पना पत्र या दृष्टि-पत्र बनाया जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली का प्रोफेशनल सहयोग इस विषय में लिया जाएगा।
- 45 से 60 दिन के बीच सभी कुलपति फिर एक बार इस विषय पर परिषद द्वारा आयोजित विमर्श करें और दृष्टि पत्र पर आम सहमति बनायें।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली-दृष्टि पत्र बनाने में तकनीकी इनपुट प्रदान करें।

परियोजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली व हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद सामूहिक रूप से करें।

अध्याय 11

अशोक सिंहल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर चिंतन

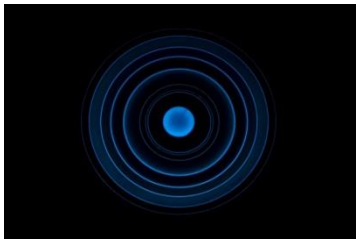

गुरुग्राम स्थापित होने जा रहे अशोक सिंहल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध कार्यक्रमों के लिए विमर्श हेतु देश सुप्रतिष्ठित विद्वानों की विशेष बैठक 11 मई 2019 को झंडेवाला मंदिर, करोलबाग, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात बैठक में प्रस्तुत की गई मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:-

1. विश्वविद्यालय के सभी कार्य करते हुए मुख्य ध्यान रखा जाए कि हर कदम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो। अनुकरण यदि करना भी है तो विवेकपूर्ण विमर्श के बाद करें।

2. वर्तमान परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद के नियमानुसार भी विश्वविद्यालय को चलाना होगा।

3. परन्तु वेद विज्ञान सम्बन्धित विषयों को भिन्न पद्धति व प्रक्रिया से संचालित करने की भी आवश्यकता है।

4. इसलिए जहां नये विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. व ए.आई.सी.टी. के अनुसार स्नातक एवं स्नातोकतर पाठयक्रम चलाए जाएं वहीं कुछ पाठयक्रम समय-सीमा और डिग्रियों तक सीमित न करके उन्हें दक्षता प्राप्ति के आधार पर संचालित किया जाए।

5. विश्वविद्यालय में संस्कृत सीखने के ऐसे पाठयक्रम चलाए जाए जिनसे व्यक्ति वेद एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने व समझने में योग्यता प्राप्त करें।

6. कुछ पाठ्यक्रम ग्रंथ आधारित संचालित हों।

7. कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षार्थियों को सायंकालीन या सप्ताहान्त में शिक्षण, अध्ययन एवं शोध के पाठ्यक्रम संचालित हों।

8. भारत एवं विदेशों में अनेक विद्वान भिन्न-भिन्न विषयों पर वेद एवं प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान-विज्ञान को प्रभावी रूप से खोज रहे हैं। विश्वविद्यालय का कार्य इन सभी विद्वानों के शोध का समन्वय करने का होना चाहिए।

9. आधुनिक विज्ञान एवं प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध ज्ञान एवं विज्ञान की प्रस्तुति आज की भाषाओं में होनी चाहिए। वर्तमान शोध पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होने चाहिए।

10. भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं का अधिकतम समावेश वैदिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में होना चाहिए। उदाहरणार्थः कुलपति को कुलगुरु कहा जाए।

11. विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध का कार्य पूर्ण तैयारी के साथ होना चाहिए न कि आधे-अधूरे प्रयास। नए पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री योग्य विद्वानों द्वारा तैयार हों।

12. वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ग्रंथों, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं एवं लेखों का प्रकाशन विश्वविद्यालय योजनाबद्ध प्रारूप में करें।

13. इन विषयों पर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा सकते हैं:- सृष्टि विज्ञान, शरीर विज्ञान, धातु विज्ञान, दृष्टि विज्ञान, भाषा विज्ञान, आहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ध्वनि विज्ञान एवं तकनीकी, संगीत विज्ञान, शिल्प तकनीकी, स्थापत्य विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मनोविज्ञान, भू-विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, गणित विज्ञान, वैदिक अर्थशास्त्र, वैदिक राजनीतिक शास्त्र, समाज विज्ञान, आत्म विज्ञान, सैन्य विज्ञान, योग विज्ञान, न्याय शास्त्र, दंड नीति, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान आदि।

14. प्रारंभ में विश्वविद्यालय इन विषयों पर कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन कर सकता हैः प्राचीन भारतीय संस्कृति (श्रृंखला), अध्ययन एवं अध्यापन की भारतीय दृष्टि, आधुनिक एवं वैदिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय ग्रंथों की चर्चा (श्रृंखला), भारतीय शोध पद्धति आदि।

15. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध कार्यक्रमों हेतु परामर्श मंडल बनना चाहिए।

16. वेद-विज्ञान से सम्बन्धित विद्वानों को चिह्नित करने के लिए 'टैलेंट सर्च मंडल' का माध्यम होना चाहिए।

अध्याय 12

परीक्षा प्रणाली में सुधार

हरियाणा के विश्वविद्यालयों के परीक्षा तंत्र में उत्तरोत्तर सुधार के उद्देश्य से हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने लगातार चिंतन मंथन किया है। इस कड़ी में परीक्षा नियंत्रकों की बैठक 29 जनवरी, 2019 को पंचकूला स्थित तकनीकी शिक्षा सदन के सभागार में सपन्न हुई। बैठक में परीक्षा तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करने के उपायों पर मंथन हुआ। इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बैठक कुरुक्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान में 8 अप्रैल, 2019 को संपन्न हुई। परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में 14 परीक्षा नियंत्रक और 2 परिषद पदाधिकारी उपस्थित रहे। परीक्षा नियंत्रकों के साथ 5 बैठकें करने के बाद छठी बैठक उसी दिन विश्वविद्यालयों के चयनित छात्र प्रतिनिधियों के साथ कुरुक्षेत्र में ही की। इस बैठक में 5 विश्वविद्यालयों के 30 चयनित छात्र प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

1. इस दौरान परीक्षा नियंत्रकों की पिछली बैठक में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन पर हुई प्रगति पर चर्चा की गई। इस बात पर चिंता जताई गई कि इस वर्ष परीक्षा सुधारों पर 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उनमें लिए गए निर्णयों पर विशेष प्रगति नहीं हो सकी।
2. परीक्षा शाखाओं में स्टाफ की कमी की ओर ध्यान आकर्षिक किया गया। बताया गया कि अधिकतर स्टाफ अस्थायी है, जो परीक्षा की गोपनीयता से अनभिज्ञ है।
3. परीक्षा मूल्यांकन में शिक्षक वर्ग कम रुचि ले रहा है, जिस कारण परिणाम घोषित करने में देर होती है। अधिक से अधिक शिक्षकों की इस काम में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
4. बैठक में उपस्थित परीक्षा नियंत्रकों ने कहा कि आउट सोर्सिंग और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा खर्च हो रहा है। सरकार को सभी विश्वविद्यालयों के एक सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए। इस पर यह भी कहा गया कि ऐसा करने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आंच आएगी।
5. परीक्षा नियंत्रकों ने कहा कि च्वाइस बेस्ड सिस्टम सिर्फ फाइलों तक सीमित है। इसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।
6. उच्च शिक्षण संस्थानों में फाइनल परीक्षा का परिणाम 7 से 40 दिनों के बीच आ रहा है।
7. रि-इवेल्यूवेशन के बारे में जानकारी दी गयी कि कुछ संस्थानों में इस प्रक्रिया को 15 दिन में तो कुछ में 3 महीने लग रहे हैं।
8. परीक्षा विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों के स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होनी चाहिए, इससे मूल्यांकन काफी जल्दी हो सकेगा। ऐसा करने पर प्रश्न-पत्रों की सेटिंग के साथ ही उनके उत्तर भी तय किए जाने चाहिए।
9. सभी विश्वविद्यालयों का साझा डाटा केंद्र बनाया जाना चाहिए। यहां से कोई भी विद्यार्थी का अपनी अंकतालिका व अन्य रिकॉर्ड प्राप्त कर सके।
10. परीक्षा नियंत्रकों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए प्राप्त किए जाने वाले शुल्क की वापसी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि पात्र विद्यार्थियों को यह शुल्क वापस किया जाना चाहिए।

परीक्षा नियंत्रकों की ओर से उपरोक्त समस्याओं के समाधान के उपाय भी सुझाए, जो इस प्रकार हैं :-

1. परीक्षा नियंत्रकों का कहना था कि परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए लघु और दीर्घ अवधि के उपायों की जरूरत है।
2. सुझाव आया कि सभी परीक्षा नियंत्रक अपने स्टाफ के साथ मिलकर माइक्रो सुझावों को एकत्रित करेंगे।
3. उनके क्रियान्वयन के लिए कुलपतियों से आग्रह करेंगे।

बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से 5 बिंदुओं पर विमर्श किया गया, जिनका ब्योरा इस प्रकार हैं :-

1. परीक्षा पूर्व (Pre-Exam)
2. परीक्षा (Examination)
3. मूल्यांकन (Evaluation)
4. परिणाम व पुनर्मूल्यांकन (Result & Re-Eevalation)
5. अंक तालिका व प्रमाण पत्र (Marksheet & Certificates)

विद्यार्थी प्रतिनिधियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा का विवरण इस प्रकार है:-

- बैठक के दौरान परिषद अध्यक्ष ने कहा कि समाज अपने श्रेष्ठ की कामना के लिए समाज विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में भेजता है। इसके लिए समाज बहुत बड़ा खर्च भी वहन करता है।
- विद्यार्थियों में समाज के प्रति कृतज्ञता की भावना का विकास होना चाहिए।
- छात्र-छात्राओं को सप्ताह में कम से कम 42 घंटे कक्षा या प्रयोगशाला में बिताने चाहिए।
- विषयेत्तर ज्ञान में वृद्धि के लिए साप्ताहिक व्याख्यान की व्यवस्था करनी चाहिए।
- छात्रों को अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञानार्जन करना चाहिए। हर विषय में रोजगार की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। विद्यार्थियों में काम के प्रति लगाव और उसके लिए कौशल का विकास जरूरी है। इस विषय को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को कम से कम इतना काम तो आना ही चाहिए वे आंख का चेकअप कर उसके लिए ऐनक का नंबर बता सकें।

इस दौरान विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने जो समस्याएं रखीं उनका विवरण इस प्रकार है :-

1. सम-विषम सेमेस्टर प्रणाली के कारण विद्यार्थी वर्ग को परेशानी हो रही है।
2. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में हो रही अनापेक्षित देरी पर चिंता जताई। छात्र प्रतिनिधियों का कहना था कि परिणाम में बहुत विलंब होने के कारण उनका कैरियर प्रभावित होता है। उन्होंने शुल्क वापसी की मांग भी की। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन का परिणाम ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों में आ जाना चाहिए।

3. छात्र प्रतिनिधियों का कहना था उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कम से कम 3 शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए।
4. शिक्षक द्वारा 20 अंक के मूल्यांकन को गलत बताया गया।
5. थ्योरी और प्रेक्टिकल में अलग-अलग उत्तीर्ण होने की शर्त हटा दी चाहिए। दोनों में संयुक्त रूप से उत्तीर्ण को ही योग्य मान लेना चाहिए।
6. छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षक पाठ्येत्तर जिम्मेदारियां बताते हैं और इस कारण वे कई बार कक्षा नहीं ले पाते।

अध्याय 13

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019

चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में 26 जून 2019 को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित शिक्षाविदों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019' की व्याख्या और क्रियान्वयन की योजना के लिये हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद की ओर से चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में 25-26 जून, 2019 को दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ-साथ सुप्रसिद्ध शिक्षाविद शामिल हुए। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों ने विमर्श में भाग लिया। स्कूलों के ऐसे अध्यापक एवं प्राचार्य जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं उन्होंने भी इसमें सहभागिता की। सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019' के अनुसार हरियाणा राज्य के लिए क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत की गई।

इससे पूर्व प्रांत के 8 प्राध्यापकों को रिपोर्ट के एक-एक अंश की प्रस्तुति करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने निर्धारित अंश का अध्ययन कर इसे शिक्षाविदों के सामने पेश किया। इस प्रकार पहले 3 सत्रों में पूरी रिपोर्ट की प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात खुली चर्चा हुई। एक सत्र में सम्पूर्ण रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गई।

26 जून के पहले सत्र में इस विषय पर चर्चा होगी कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019' हरियाणा प्रांत के लिये किस प्रकार से लागू की जाए। एक सत्र में समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा प्रांत में अमल में लाने के लिए योजना का प्रस्ताव बनाया गया। विमर्श के समापन सत्र में मुख्यमंत्री के सम्मुख सम्मेलन के समीक्षा और क्रियान्वयन के बिंदु प्रस्तुत किये गए। इस विषय पर मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ।

अध्याय 14

गीता संभाषण प्रतियोगिता

जींद स्थित चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में 6 मार्च 2019 को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित संभाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के साथ कुलपति डॉ. राजबीर सिंह सोलंकी एवं दूसरे अधिकारी।

हरियाणा राज्च उच्च शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश योजना के अंतर्गत गीता पर संभाषण प्रतियोगिता करवाई। 6 मार्च, 2019 को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द के लक्ष्मीबाई छात्रावास में 'गीता के अध्याय अनुसार सम्भाषण (स्पीच) की प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. राजबीर सोलंकी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुल 40 प्रतिभागियों ने 8 से 10 मिनट के सम्भाषण में गीता के अध्याय अनुसार मौखिक रूप से प्रस्तुतियां दीं।

शिक्षा का अर्थ

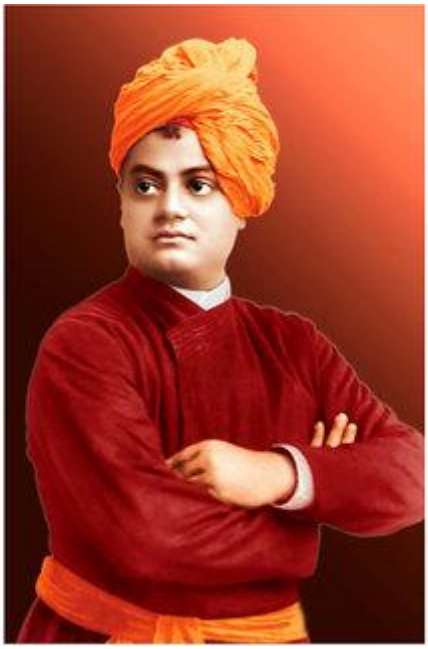

सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति में न्यायप्रियता, सत्यप्रियता एवं कार्य दक्षता उत्पन्न कर सके। हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सके। ऐसी शिक्षा जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचने और करने को कहती हो। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिसका अनुसरण करने से व्यक्ति अपने परिवार, समाज व देश का गौरव बढ़ा सके। युवाओं को ऐसी प्रचंड इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत न कर सके।

- **स्वामी विवेकानंद**